भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3870

दिनांक 11.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक बाहन

3870. डॉ. लता वानखेड़े:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2025-2026 के दौरान नव-प्रारंभ की गई पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती के संबंध में प्राप्त कुल प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत एक वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक सब्सिडी प्राप्त और पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और इलेक्ट्रिक बसों की कुल संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश के भीतर वाहन खरीदारों और वितरण शृंखलाओं का संचालन करने वाले मूल उपकरण निर्माताओं को प्रत्यक्ष वितरित किए गए कुल मांग प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरी मार्गों पर चलने वाली सार्वजनिक इलेक्ट्रिक परिवहन बसों की परिचालन विश्वसनीयता और बैटरी प्रदर्शन की निगरानी की है; और

(ङ) मध्य प्रदेश के द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में स्वच्छ ऊर्जा परिवहन प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में 94,277 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) तैनात किए गए।

(ख) और (ग): वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मध्य प्रदेश में 88,209 इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को सब्सिडी प्रदान की गई, जिसका विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए कोई इलेक्ट्रिक बस आवंटित नहीं की गई है।

मध्य प्रदेश में वाहन क्रेताओं तथा डिलीवरी श्रृंखला में कार्यरत मूल उपकरण विनिर्माताओं को सीधे वितरित की गई मांग प्रोत्साहन की कुल राशि का विवरण केंद्रीय स्तर पर संधारित नहीं किया जाता है।

(घ): भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है।

(ङ): देश में स्वच्छ ऊर्जा परिवहन प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के द्वि-स्तरीय एवं त्रि-स्तरीय शहरों सहित देशभर में निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन किया गया है:

(i) भारत में हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम, चरण-II: सरकार द्वारा इस स्कीम को 01.04.2019 से 31.03.2024 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए 11,500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय सहयोग के साथ कार्यान्वित किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया एवं ई-चौपहिया के लिए मांग प्रोत्साहन तथा ई-बसों एवं ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) की स्थापना के लिए अनुदान प्रदान किया गया। फेम-2 के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया एवं ई-चौपहिया सहित लगभग 16.72 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में सहायता प्रदान की गई है तथा तथा विभिन्न शहरों के लिए 6,862 ई-बसें स्वीकृत की गई थीं, जिनमें से दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार 5,299 ई-बसें तैनात की जा चुकी हैं। इस स्कीम के अंतर्गत ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) की स्थापना हेतु 912.50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

(ii) भारत में ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो): सरकार द्वारा भारत में ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए इस स्कीम की अधिसूचना दिनांक 23.09.2021 को उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों, जिनमें ईवी भी शामिल हैं, के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से 25,938 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ जारी की गई।

(iii) राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम: सरकार द्वारा देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए 18,100 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ दिनांक 09.06.2021 को पीएलआई स्कीम की अधिसूचना जारी की गई। इस स्कीम का उद्देश्य 50 गीगावाट घंटा एसीसी बैटरियों के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।

(iv) पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम: 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली इस स्कीम की अधिसूचना दिनांक 29.09.2024 को जारी की गई। इस स्कीम के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस तथा ई-एम्बुलेंस सहित लगभग 28.30 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के अंतर्गत परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए भी अनुदान उपलब्ध है। स्कीम के अंतर्गत 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए 4,391 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें से 14,000 ई-बसों का आवंटन किया जा चुका है। देशभर में ईवीपीसीएस की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

(v) पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम: इस स्कीम की अधिसूचना दिनांक 28.10.2024 को 3,435.33 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जारी की गई। इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती में सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में ई-बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें भी की गई हैं:–

(i) इलेक्ट्रिक वाहनों तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी की दर घटाकर 5% कर दी गई है।

(ii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने घोषणा की है कि बैटरी चालित वाहनों को हरी लाइसेंस प्लेट प्रदान की जाएगी तथा उन्हें परमिट संबंधी आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

(iii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को ईवी पर सड़क कर में छूट प्रदान करने संबंधी परामर्श जारी किया है, जिससे ईवी की प्रारंभिक लागत कम करने में सहायता मिलेगी।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मध्य प्रदेश में पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत जिले-वार प्रोत्साहित ई-दुपहिया एवं ई-तिपहिया वाहनों की संख्या:

जिला	ई-दुपहिया	ई-तिपहिया	कुल
आगर मालवा	64		64
आलीराजपुर	65		65
अनुपपुर	204	19	223
अशोकनगर	1,149	13	1,162
बालाघाट	772	13	785
बड़वानी	409	2	411
बेतुल	1,023	20	1,043
भिंड	1,282	141	1,423
भोपाल	6,509	113	6,622
बुरहानपुर	226	2	228
छतरपुर	1,160	23	1,183
छिंदवाड़ा	2,606	77	2,683
दमोह	671	138	809
दतिया	513	58	571
देवास	2,078	61	2,139
धार	1,233	22	1,255
डिंडोरी	62	60	122
गुना	2,392	33	2,425
ग्वालियर	8,987	489	9,476
हरदा	790	1	791
इंदौर	11,347	1,493	12,840
जबलपुर	6,905	1,008	7,913
झाबुआ	86		86
कटनी	757	567	1,324
खंडवा	376	17	393
खरगोन	499	20	519
मैहर	13	8	21
मंडला	280	24	304
मन्दसौर	1,818	14	1,832

मऊगंज	5	3	8
मुरैना	1,949	199	2,148
नर्मदापुरम	1,662	26	1,688
नरसिंहपुर	1,909	58	1,967
नीमच	772	3	775
निवाड़ी	7	1	8
पंधुरना	12		12
पन्ना	146	50	196
रायसेन	953	21	974
राजगढ़	782	5	787
रतलाम	1,704	23	1,727
रीवा	1,130	331	1,461
सागर	2,285	400	2,685
सतना	1,117	383	1,500
सीहोर	1,711	19	1730
सिवनी	1,020	19	1039
शहडोल	738	55	793
शाजापुर	847	21	868
श्योपुर	588	10	598
शिवपुरी	1,708	37	1,745
सीधी	241	44	285
सिंगरौली	257	23	280
टीकमगढ़	550	32	582
उज्जैन	3,490	132	3,622
उमरिया	176	29	205
विदिशा	1,805	9	1,814
कुल	**81,840**	**6,369**	**88,209**

******